



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2012/फाल्गुन 11, 1933

No. 316]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2012/PHALGUNA 11, 1933

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2012

का.आ. 356(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य के मध्य सन् 2006 का मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने आदेश, तारीख 18 फरवरी, 2010, और तारीख 29 मार्च, 2010 द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा माननीय डॉ. ए. एस. आनंद, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष, अध्यक्ष के परामर्श से तमिलनाडु और केरल राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य से एक सदस्य और अध्यक्ष के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो तकनीकी सदस्यों को, जो विवाद से संबंधित न हों, से मिलकर बनने वाली सशक्त समिति का गठन करने के लिए निदेशित किया था;

और, सशक्त समिति को उसके समक्ष वाद के पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी विवादकों पर, बिना उन विवादकों तक सीमित रहते हुए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, सुनवाई करनी थी और अपने गठन से छह मास के भीतर, यथा संभव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, सशक्त समिति, अधिसूचना सं. का.आ. 992(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2010 द्वारा गठित की गई थी;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2659(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2010, का.आ. 910 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 और का.आ. 2267(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2011 द्वारा, समय-समय पर सशक्त समिति की अवधि 29 फरवरी, 2012 तक विस्तारित कर दी;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन् 2006 के मूल वाद सं. 3 के मामले में अपने तारीख 27 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा सशक्त समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय पुनः 30 अप्रैल, 2012 तक विस्तारित कर दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए सशक्त समिति की अवधि को 30 अप्रैल, 2012 तक के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. 11/2/2010-बीएम]

जी. मोहन कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, , 2012

S.O. 356(E).—Whereas in the matter of Original Suit No. 3 of 2006, between State of Tamil Nadu V/s State of Kerala, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Orders, dated the 18th February, 2010 and the 29th March, 2010, directed the Central Government to set up by notification in the Official Gazette, an Empowered Committee, comprising of Hon'ble Dr. A.S. Anand, former Chief Justice of India as the Chairman, one Member each to be nominated by State of Tamil Nadu and Kerala, in consultation with the Chairman, and two technical experts, not connected with the dispute, to be nominated by the Central Government, in consultation with the Chairman;

And whereas the Empowered Committee was to hear to the parties to the suit on all issues raised before them without being limited to issues that have been raised before the Hon'ble Supreme Court and the Committee was to furnish a report, as far as possible, within a period of six months from its constitution;

And whereas the Empowered Committee was constituted *vide* notification number S.O. 992(E), dated the 30th April, 2010;

And whereas the Central Government, on directions of the Hon'ble Supreme Court, *vide* notification number S.O. 2659(E), dated the 28th October, 2010, S.O.910(E), dated the 29th April, 2011 and S.O. 2267(E), dated the 30th September, 2011, extended the term of Empowered Committee from time to time up to 29th February, 2012;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in the matter of Original Suit No. 3 of 2006, *vide* its Order dated the 27th February, 2012 has again extended the time for submission of the final report by the Empowered Committee till 30th April, 2012;

Now, therefore, for implementing the said directions of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby extends the term of Empowered Committee up to 30th April, 2012.

[F.No. 11/2/2010-BM]

G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy.